गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल में मूल्यवान दवाइयों की हेरा-फेरी

733. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर :**
श्री हरि शंकर भाभड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, दिल्ली में मूल्यवान दवाइयों की हेरा-फेरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

Bungling in costly medicines in the Govind Ballabh Pant Hospital

733. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
SHRI HARISHANKER BHABHDA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received any reports regarding bungling in costly medicines in the Govind Ballabh Pant Hospital, Delhi; and

(b) if so, what are the details in this regard and what action Government have taken in the matter?]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार निरोधी विभाग द्वारा जांच की गई है और यह प्रशासन इस जांच-रिपोर्ट पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ कर रहा है। जांच के निष्कर्षों और उन पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में मूल्यवान दवाइयों की बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी के बारे में शिकायतें मिलने तथा समाचार पत्रों में छपी खबरों के परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन ने इस मामले को अपने भ्रष्टाचार-निरोधी विभाग को भेजा जिसने विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं :—

(क) कतिपय मामलों में डाक्टरों ने रोगियों को इंजेक्शनों के नुस्खे नहीं लिखे थे किन्तु ये जारी किए गये दिखलाए गये थे।

(ख) एक रोगी 3-6-75 को भर्ती किया गया था परन्तु इंजेक्शनों का लगाया जाना 1-6-75 से दिखलाया गया था।

(ग) 15-6-75 से 19-6-75 तक वार्ड नं० 8 में केनामाइसिन इंजेक्शन का स्टाक "शून्य" था परन्तु इस अवधि में भी एक रोगी को इंजेक्शन जारी किए गये थे।

भ्रष्टाचार-निरोधी विभाग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने जो निर्णय लिए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) गबन सहित मूल्यवान इंजेक्शनों की चोरी करने के बारे में फौजदारी कार्यवाही आरम्भ की जाए;

(2) अन्य इंजेक्शनों और दवाइयों की चोरी के बारे में सिस्टर इंचार्ज के विरुद्ध व्यस्कों के लिए निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही आरम्भ की जाए।

1[ ] English translation.

(3) जिन पांच नर्सों ने स्टाक पुस्तिकाओं में वस्तुतः गलत प्रविष्टियां की थी उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ।

(4) चूंकि अस्पताल के अन्य वार्डों विभागों में भी चोरी किए जाने की संभावना है, इसलिए सचिव (चिकित्सा) दिल्ली प्रशासन से यह कहा गया है कि वे औषधियों आदि के जारी करने और देने सम्बन्धी क्रियाविधियों तथा पद्धतियों में सुधार करने के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करें ।

(5) वार्ड नम्बर 8 के सम्बन्ध में लगभग 6 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि की ओर आगे गहरी जांच की जाए और यदि भ्रष्टाचार निरोधी विभाग के जांच अधिकारी आवश्यक समझें तो किसी और वार्ड की भी जांच कर लें ।

(6) दिल्ली प्रशासन के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले अस्पतालों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के हिसाब-किताब की विशेष लेखा-परीक्षा की जाए ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes.

(b) An inquiry has been conducted by the Anti-Corruption Department of Delhi Administration who are initiating necessary follow up action on the report of the inquiry. The details of findings of the enquiry and the action proposed to be taken are given in the statement attached.

Statement

In the wake of complaints as well as Press Reports about large scale bungling in costly medicines in the G.B. Pant Hospital, the Delhi Administration referred the case to their Anti-Corruption Department who, after making detailed enquiry, have made the following observations:—

(a) In certain cases, doctors had not prescribed injections to the patients but these were shown to have been issued.

(b) One patient was admitted on 3.6.75 but the consumption of the injections had been shown with effect from 1.6.75.

(c) There had been 'Nil' stock of injection Kenamycin in Ward No. VIII from 15.6.75 to 19.6.75 but one patient had been issued injections during this period as well.

After considering the report of the Anti-Corruption Department, the Delhi Administration has decided as under:—

(i) Regarding pilferage of costly injections, involving misappropriation criminal proceedigs may be started.

(ii) Regarding pilferage of other injections and medicines, penalty proceedings for major may be initiated against the Sister incharge.

(iii) Institutions of appropriate proceedings against 5 Nurses, who had actually made false entries in the stock books has been recommended.

(iv) As the pilferage is likely to be prevalent in other Wards|Departments of the Hospital Secretary (Medical) Delhi Administration has been asked to constitute a Committee to go into the overall question of improving procedures and practices relating to the issue and administration of drugs etc.

(v) A deeper and further probe in Ward No. VIII may be undertaken for the entire period of about 6 years and in any other ward considered necessary by the

†[ ] English translation.

Inquiry Officer of the Anti-Corruption Department.

(vi) Special Audit in Hospitals under the administrative control of Delhi Administration for the last two financial years to be undertaken.]

Procurement of Wheat

734. SHRI HARISHANKAR BHABHDA:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the procurement of wheat this year is likely to exceed the target;

(b) whether Government have made adequate arrangements for the storage of wheat proposed to be procured; and

(c) if so, what are the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) No target for procurement of wheat has been fixed in the current Rabi marketing season. A total quantity of about 54.28 lakh tonnes of wheat has been procured so far.

(b) and (c) The storage capacity (both owned and hired) with Food Corporation of India as on 1.6.78 was of the order of 21.02 million tonnes which included CAP Storage of 7.24 million tonnes. Optimum utilization of the existing capacity is being made by increasing the stack heights. A project for construction of storage capacity of 3.6 million tonnes has been undertaken with the assistance of World Bank. Another project for the construction of 4.25 lakh tonnes storage capacity with the assistance of European Economic Community has also been finalised. A scheme for the construction of godowns by private parties and hiring by Food Corporation of India is also being implemented. A capacity of 2.7 million tonnes has already been taken over and a further capacity of 1.1 million tonnes under construction is likely to be completed and taken over shortly. As a further extension of this scheme, a programme for the construction of additional capacity of 2 million tonnes has also been launched.

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का मंजूर किया जाना

735. श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री हरि शंकर भाभड़ा :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को मंजूर किये जाने के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं, जिनका सर्वेक्षण 30 जून, 1978 तक पूरा हो चुका था ;

(ग) शेष अनधिकृत कालोनियो के सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाली इन कालोनियों के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों से सुझाव आमंत्रित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?